पहाड़ी राज्यों का विकास सेवा क्षेत्र में संभव

भरत झुनझुनवाला

अर्थव्यवस्था के तीन प्रमुख क्षेत्र होते हैं : कृषि, मैन्युफैक्चरिंग एवं सेवा। मैन्युफैक्चरिंग में कागज़, सीमेंट, कार इत्यादि का उत्पादन आता है जो कि भौतिक वस्तुएं हैं। सेवा क्षेत्र में होटल, संगीत, यातायात, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, बैंक आदि आते हैं, जिनमें किसी माल का उत्पादन नहीं होता लेकिन उपभोक्ता किसी सेवा की खपत करता है। वर्ष 1951 में हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का हिस्सा 56 प्रतिशत, मैन्युफैक्चरिंग का 14 प्रतिशत और सेवा का 30 प्रतिशत था। वर्तमान में कृषि का हिस्सा 56 प्रतिशत से घटकर मात्र 16 प्रतिशत रह गया है जबकि मैन्युफैक्चरिंग 14 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत पर पहुच गई है और सेवा क्षेत्र 30 प्रतिशत से बढ़कर 54 प्रतिशत पर पहुच गई है। अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान तेजी से गिर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एवं सेवा क्षेत्र बढ़ रहे हैं। कृषि के हिस्से में गिरावट आने का मुख्य कारण है कि विश्व में कृषि उत्पादों की मांग सीमित है। विश्व की जनसंख्या में मामूली वृद्धि हो रही है। तदनुसार खाद्य पदार्थों की खपत में भी मामूली ही वृद्धि हो रही है। इसमें कुछ वृद्धि अंडे एवं मीट की खपत के कारण हो रही है लेकिन वर्तमान में स्वास्थ्य कारणों से तमाम लोग शाकाहारी भोजन को अपना रहे हैं। साथ-साथ ब्राज़ील जैसे देशों में गन्ने से पेट्रोल बनाया जा रहा है लेकिन इसकी लागत बहुत ज्यादा आती है। इसलिए कृषि उत्पादों की मांग कम है। कृषि क्षेत्र में गिरावट वैश्विक स्तर पर हो रही है।

मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति सामान्य है। वह इसलिए कि किसी भी परिवार द्वारा उत्पादित माल की खपत की एक सीमा होती है। जैसे आप के घर में यदि एक फ्रिज है तो आप दूसरा फ्रिज नहीं खरीदेंगे। फ्रिज, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन खरीद लेने के बाद आप के द्वारा उत्पादित माल की खपत में वृद्धि कम ही होगी। तुलना में सेवा क्षेत्र में खपत उत्तरोतर बढ़ती जाती है। जैसे आप वर्ष में एक बार विदेश पर्यटन के स्थान पर पांच बार भी कर सकते हैं। आप नए-नए संगीत को सुन सकते हैं और यदि आप चाहें तो किसी कंप्यूटर प्रोग्रामर को कह सकते हैं कि आपकी इच्छा अनुसार कोई एप अथवा सिनेमा बनाए। इसलिए सेवा क्षेत्र में खपत की अपार संभावनाएं हैं और इस क्षेत्र में वृद्धि होती जा रही है। इसलिए आज अमेरिका जैसे विकसित देशों की आय में कृषि का हिस्सा मात्र, 1 प्रतिशत, मैन्युफैक्चरिंग का 19 प्रतिशत और सेवा का 80 प्रतिशत है। हम भी इसी दिशा में चल रहे हैं।

मैन्युफैक्चरिंग में पहाड़ी क्षेत्रों की अनुकूलता कम है। किसी माल के उत्पादन में ढुलाई का खर्च महत्वपूर्ण होता है। पहाड़ी क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग के उद्योग लगाने के लिए आपको कच्चे माल को मैदान से पहले पहाड़ पर लाना होगा और फिर बनाए हुए माल को पुन: नीचे ले जाना होगा। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े शहर कम होते हैं। अत: यदि आपकी बिजली की मोटर जल गई तो पहाड़ी क्षेत्र में दूसरी मोटर लाकर उसको लगाने में तीन दिन का समय लग जाता है जबकि मैदानी क्षेत्र में यह कार्य छह घंटे में हो सकता है। बिजली की सप्लाई भी मैदानी क्षेत्रों में तुलना में अच्छी होती है। अत: पहाड़ी क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग के विस्तार की संभावनाएं कम हैं। देखा गया कि हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में बद्दी और उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र काशीपुर और जम्मू कश्मीर के मैदानी क्षेत्र जम्मू में ही मैन्युफैक्चरिंग उद्योग लग रहे हैं। यानी पहाड़ी राज्य के भी जो मैदानी क्षेत्र हैं, उनमें ही मैन्युफैक्चरिंग उद्योग लग रहे हैं। प्रमुख पहाड़ी क्षेत्र में उद्योगों का सर्वथा अभाव है। इसका एक पक्ष यह भी है कि यदि पहाड़ी राज्य मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर बढ़ते हैं तो पहाड़ी राज्यों के शुद्ध पहाड़ी क्षेत्रों से राज्य के ही मैदानी क्षेत्र को पलायन जारी रहता है। जैसे उत्तराखंड के चमोली जिले के युवक आज उत्तराखंड के ही मैदानी क्षेत्र काशीपुर में जाकर उद्योगों में रोजगार कर रहे हैं। इस पलायन का सामरिक महत्व भी है। यदि किसी परिस्थिति में देश के पहाड़ी क्षेत्र में आक्रमण हुआ तो हम पायेंगे की हमारे पहाड़ खाली हो चुके हैं। हमारी सेना को समर्थन एवं सहायता और सूचना देने के लिए स्थानीय लोगों का नितांत अभाव है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर आगे बढ़ना कठिन दिखता है।

तुलना में सेवा क्षेत्र में परिस्थिति बिल्कुल बदल जाती है। यहां जो पहाड़ की दुर्गमता है, उसके साथ पहाड़ का सौंदर्य भी सामने आता है। जैसे स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में उन्होंने यूनिवर्सिटी एवं अस्पताल बनाए हैं। नैनीताल के पास भवाली में किसी समय क्षय रोग के मरीजों के लिए सैनीटोरियम बनाया गया था। सोच थी कि वहां की शुद्ध वायु एवं प्राकृतिक वातावरण में मरीज को स्वास्थ्य लाभ शीघ्र होगा। अत: पहाड़ी राज्य यदि सेवा क्षेत्र जैसे सॉफ्टवेयर पार्क, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, इत्यादि पर ध्यान दें तो इनकी जो दुर्गमता है, वह नुकसानदेह होने के स्थान पर लाभप्रद हो जाएगी। पहाड़ी क्षेत्रों में हवाई पट्टियां बनाई जा सकती हैं जहां पर व्यक्ति आसानी से पहुंच सकता है। जैसे केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सर्विस चलती है।

संपादकीय

आखिरकार फांसी चढ़े हत्यारे

निर्भया कांड के चारों दोषी आखिरकार फांसी के फंदे पर चढ़ा दिए गए। इस तरह पिछले सात साल से भी ज्यादा समय से चला आ रहा यह मामला अपने मुकाम तक पहुंचा, जिससे न सिर्फ पीड़िता के परिजनों ने बल्कि देश भर के उन तमाम लोगों ने राहत की सांस ली है, जो इस हादसे के बाद सड़क पर स्त्री की सुरक्षा और सम्मान को लेकर चिंतित थे। हालांकि उनके भीतर इस बात की कसक भी है कि न्याय मिलने में सात साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 की रात चलती बस में निर्भया के साथ छह लोगों ने सामूहिक बलात्कार और क्रूरता की अति कर दी थी, जिससे हफ्ते भर जूझने के बाद उसकी मौत हो गई थी।

बलात्कारियों में से एक के नाबालिग होने की वजह से उस पर जूवेनाइल के तहत मामला चला जबकि एक ने जेल में आत्महत्या कर ली। बाकी चारों दोषियों ने फांसी से बचने के लिए सभी संभव कानूनी विकल्पों का पूरा इस्तेमाल किया और गुरुवार की रात तक इस मामले की सुनवाई चली। इन चारों को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद तीन बार सजा की तामील के लिए तारीखें तय हुई लेकिन फांसी टलती गई।

लोगों में इस देरी से गुस्सा था लेकिन अंतत: शुक्रवार की सुबह उन्हें फांसी दे दी गई। निर्भया कांड के बाद देश में जबर्दस्त आक्रोश फैला और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर एक आंदोलन की शुरुआत हो गई। सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बने कानूनों को सख्त रूप देने का दबाव बढ़ा। आखिरकार इस संबंध में सुझाव देने के लिए जस्टिस वर्मा कमिटी का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिशों के अनुरूप कई नियम-कायदे भी बने। लेकिन कुल मिलाकर हालात अब भी ज्यादा नहीं बदले हैं।

बलात्कार के मामले पहले से कुछ बढ़ गए हैं। अलबत्ता इस बीच इतना जरूर हुआ है कि पहले से ज्यादा महिलाएं अपने साथ हुए अत्याचार की सूचना देने सामने आ रही हैं। पुलिस भी कम से कम बड़े शहरों में उनकी शिकायत पर पहले से ज्यादा ध्यान देने लगी है। लेकिन अपराधियों को दोषी ठहराए जाने की दर आज भी पुराने मुकाम पर ही अटकी हुई है। रेप के मामलों में आज भी 27 फीसदी आरोपियों को ही सजा हो पा रही है। दोषी बड़ी संख्या में छूट जा रहे हैं। पुलिस अब भी ऐसे सबूत जुटाने में अक्षम है जो सुनवाई के दौरान ठोस साबित हों। जब यौन अपराधों पर नया कानून पारित हुआ था तो सरकार ने वादा किया था कि पुलिस को जांच की आधुनिकतम तकनीकों से लैस किया जाएगा। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो यह अब तक नहीं हुआ है। कमियां और भी कई स्तरों पर हैं। असल बात हमारे सिस्टम को महिलाओं के मामले में संवेदनशील और मुस्तैद बनाने की है, ताकि सजा दिलाने की दर में वृद्धि हो। सजा कितनी मिलती है, इससे ज्यादा अहम बात यह है कि सजा कितनी जल्दी मिलती है। जल्दी न्याय होने से ही अपराधियों में खौफ पैदा होगा।

सू- दोकू क्र.069

	1			4			7	
		6	9		2			1
	7			6		8		2
1							8	
	8			5		2		3
3		2			4		1	
	3		2			4		
		8		1	6			7
9			4				2	

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गों का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक भर सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र 68 का हल

3	9	6	8	2	5	4	7	1
8	2	5	1	7	4	6	3	9
7	1	4	6	9	3		2	5
1	8	9	3	6	7	2	5	4
2	6	7	5	4	8	1	9	3
5	4	3	9	1	2	7	8	6
6	7	2	4	3	9	5	1	8
9	5	1	7	8	6	3	4	2
4	3	8	2	5	1	9	6	7

अलगाव में बचाव

भारत जैसे सघन व बड़ी आबादी वाले देश में सीमित संसाधनों के चलते कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में सामाजिक अलगाव ही प्रभावी उपाय नजर आता है। यहां तक कि दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश और कोरोना वायरस के स्रोत चीन ने सख्ती से इस नीति का पालन किया और उसके नतीजे सामने आये। चीन में नये मरीजों की संख्या में कमी का दावा किया जा रहा है। भारत एक सांस्कृतिक प्रधान व सामूहिकता के आयोजन का देश है। यह जो उसकी ताकत थी, वायरस के फैलाव में यही सामाजिकता एक चुनौती बनती नजर आ रही है। नि:संदेह भारत सरकार ने समय रहते कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए एहतियाती कदम उठाये हैं। हवाई अड्डों व बंदरगाहों पर विदेशियों के आवागमन पर रोक तथा थल सीमाओं पर नियंत्रण निगरानी का प्रयास किया। सामाजिक अलगाव के लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में अवकाश, सिनेमाघर बंद कराने तथा भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक आयोजनों पर रोक; नि:संदेह वायरस के प्रसार पर अंकुश लगायेगा। भले ही संक्रमित लोगों का आंकड़ा सौ पार कर गया हो, मगर सरकार व चिकित्सा-तंत्र इसका प्रसार रोकने को कटिबद्ध है। मगर अभी चुनौती कम नहीं हुई है। अभी वे लोग ही चिकित्सा-तंत्र व एजेंसियों के संपर्क में आये हैं जो विदेशों से आये अथवा जो विदेशियों से संक्रमित हुए। सघन जांच देश की राजधानी और प्रमुख राज्यों की राजधानियों में ही हुई है। यदि यह रोग बिना किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आये बिना दूरदराज के इलाके में पनपता है तो इससे निपटना बड़ी चुनौती होगी। बहरहाल, इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण एशियाई देशों के राष्ट्र प्रमुखों से कोरोना वायरस से निपटने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संवाद एक सार्थक पहल है। भारतीय सीमा से लगे देशों में इस रोग का विस्तार देर-सवेर हमारे लिये ही मुश्किलें खड़ी कर सकता है।

नि:संदेह यह निरंतर सतर्कता बढ़ाने का वक्त है। किसी भी तरह की कोताही महंगी पड़ सकती है। जरूरी है केंद्र व राज्य सरकार की रीति-नीति में एकरूपता हो। यदि दिल्ली में कोई कदम उठाया जाता है तो इसकी सीमाओं से जुड़े राज्यों में भी ऐसे ही कदम उठाये जायें। समय की मांग है कि गाहे-बगाहे उभर आने वाले वायरस रोगों से निपटने के लिये दूरगामी रणनीति बने। जितना जल्दी संभव हो एक प्रोटोकॉल बने। नि:संदेह सामाजिक दूरियों के साथ चिकित्सा-तंत्र को मजबूत बनाना अपरिहार्य है। आम अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं का क्या हाल है, यह किसी से छिपा नहीं है। शहरी क्षेत्रों में तो फिर भी कुछ चिकित्सा सुविधाएं मौजूद हैं, मगर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की बदहाली जगजाहिर है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सक्रियता को नियंत्रित करना भी आसान नहीं होगा, वह भी तब जब फसल काटने व उसे मंडियों तक पहुंचाने की बात आएगी। जरूरी है कि बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाये जायें। सोशल मीडिया पर जारी भ्रामक प्रचार से इतर प्रामाणिक व कारगर जानकारी विश्वस्त माध्यमों से पहुंचे। लोगों के लिए मास्क व सैनेटाइजर गुणवत्ता के साथ सहज उपलब्ध हों। साथ ही देश के दूरदराज के इलाकों में कोरोना वायरस टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध हों। हमारे देश में सवा अरब लोगों के मद्देनजर टेस्ट लैबों की संख्या नाकाफी है। अभी हमने सिर्फ विदेशों से आये लोगों और उनके संपर्क में आये लोगों की ही जांच की है। नि:संदेह वायरस के लिए स्क्रीनिंग और सैंपल टेस्ट का दायरा बढ़ाने की सख्त जरूरत है। यदि विदेश से न आने और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में न आने के बावजूद किसी व्यक्ति में यह वायरस पाया जाता है तो मुश्किलें बढ़ेंगी। वह तब जब टेस्ट जांच की सुविधा चुनिंदा शहरों में ही हैं। चिंता की बात यह है कि यह भारत में सामान्य फ्लू का भी मौसम है, जिसमें खांसी-जुकाम व बुखार की आम बात होती है। समय रहते ऐसी जगहों का भी चयन किया जाना चाहिए जहां रोग के बढ़ने पर लोगों को अलग रखा जा सके। नवीन मिश्रा।